ऑल यूनियंस एंड एसोसिएषंस ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी)

सं. यूए/2021/38 **दिनांक 27.09.2021**

सर्कुलर

सेवा में

जनरल संकेटरीज
एयूएबी के घटक

प्रिय साथियों,

एयूएबी की एक बैठक 23.09.2021 और 25.09.2021 को आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित साथियों ने भाग लिया।

बीएसएनएलईयूः	कॉम. पी. अभिमन्यु, जीएस और संयोजक, एयूएबी।
एनएफटीईः	कॉम. चंदेश्वर सिंह, जीएस और अध्यक्ष, एयूएबी और कॉम. राजामौली, कोषाध्यक्ष
एआईजीईटीओएः	कॉम. सुनील गौतम, एजीएस
एसएनईएः	कॉम. के. सेबेस्टिन, जीएस, और कॉम. ए. ए. खान, अध्यक्ष
एआईबीएसएनएलईएः	कॉम. राजपाल शर्मा, एजीएस
एसईडब्ल्यूए बीएसएनएलः	कॉम. एन डी राम, जी.एस.
एफएनटीओः	कॉम. कॉम. के जयप्रकाश, जीएस और कॉमरेड मोहिंदर सिंह, एजीएस।
बीएसएनएल एमएसः	कॉम. सुरेश कुमार, जी.एस.
बीएसएनएल एटीएमः	कॉम. रेवती प्रसाद, एजीएस
टीईपीयूः	कॉम. राशिद खान, एजीएस
बीएसएनएल ओएः	कॉम. एच पी सिंह, जी.एस.

बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष कॉम. चंदेश्वर सिंह ने की। कॉम. पी. अभिमन्यु, संयोजक ने सभी का स्वागत किया और बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर जानकारी दी। बैठक ने सर्वसम्मति से 21, 22 और 23 सितंबर, 2021 को जंतर मंतर, नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय धरना को एक ऐतिहासिक सफलता बनाने के लिए सदस्यों और नेताओं को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

एयूएबी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय धरने को अस्थिर करने के लिए बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा 17.09.2021 को जारी प्रतिगामी पत्र पर बैठक में गंभीर अपत्ति व्यक्त की। पत्र में तीन दिवसीय धरने को तोड़ने के लिए सीजीएम को निर्देश जारी किए गए थे। बैठक ने माना कि, यह पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है, जिसने फैसला सुनाया है कि भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एयूएबी को, इस पत्र को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि, एयूएबी नेताओं को 24.09.2021 को ही सीएमडी बीएसएनएल से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और पत्र को वापस लेने की मांग करनी चाहिए। (तदनुसार, एयूएबी के प्रतिनिधियों ने सीएमडी बीएसएनएल से मुलाकात की और पत्र को वापस लेने की मांग की। लेकिन, सीएमडी बीएसएनएल ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।)

इसके बाद, एयूएबी द्वारा अपनाई जाने वाली भावी कार्रवाई के बारे में चर्चा हुई। लेकिन समय की कमी के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक पुनः दिनांक 25.09.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई। आगे की कार्रवाई पर चर्चा जारी रही। 23.10.2019 को रिवाइवल पैकेज की मंजूरी के बाद भी बीएसएनएल के वित्तीय पुनरुद्धार के लिए कदम उठाने में और कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को निपटाने में बीएसएनएल प्रबंधन की विफलता पर सभी नेताओं ने अपनी निराशा और गहरी पीड़ा व्यक्त की। बल्कि, बैठक में देखा गया कि प्रबंधन की अक्षमता के कारण बीएसएनएल का संकट और गहरा गया है। बैठक का सर्वसम्मत मत है कि श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, कंपनी की चौतरफा विफलता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

23.10.2019 को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के तुरंत बाद, एयूएबी ने मांग की थी कि प्रबंधन को सभी 49,300 4जी संगत बीटीएस के उन्नयन के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। **अगर ऐसा किया जाता, तो बीएसएनएल अप्रैल, 2020 से पहले ही अपनी पैन इंडिया 4जी सेवा शुरू कर देता, वह भी बिना कोई नया उपकरण खरीदे।** लेकिन, एयूएबी द्वारा 49,300 टावरों के तत्काल उन्नयन के लिए बार–बार अपील करने के बावजूद, श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल ने 4जी सेवाओं को शुरू करने के लिए एक के बाद एक तारीख, अर्थात् 01.01.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, आदि देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, ने टावरों के उन्नयन के लिए तत्कालीन निदेशक (सीएम) द्वारा उठाए गए कदमों का कड़ा विरोध भी किया था। पहले के प्रबंधन ने दूरदृष्टि से 4जी संगत उपकरण खरीदे थे और सिस्टम में स्थापित किए थे। लेकिन, बीएसएनएल के वर्तमान सीएमडी श्री पी. के. पुरवार, उन उपकरणों को अपग्रेड करने और 4 जी सेवाओं को लॉन्च करने में भी सक्षम नहीं हुए। यह श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल में क्षमता की कमी को साबित करता है।

श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, ने घोषणा की थी कि, मार्च, 2020 से, अगर वीआरएस सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो वह हर महीने की नियत तारीख पर वेतन के वितरण को नियमित करेंगे। लेकिन, 80,000 कर्मचारियों के वीआरएस पर चले जाने के बाद भी नियत तारीख पर वेतन का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, ने अब यह ज्ञापित किया है कि, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है।

श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल ने पदभार संभालने के बाद वेतन संषोधन को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है, जबकि पूर्ण बीएसएनएल बोर्ड ने वेतन संशोधन की सिफारिश की है। यहां तक कि नॉन–एक्जीक्यूटिवों के लिए वेतन वार्ता शुरू करने के डीओटी के निर्देश को भी वर्तमान सीएमडी ने रोक दिया है।

श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल द्वारा एयूएबी, सीजीएम और फील्ड इकाइयों द्वारा दिए गए सुझावों को सुने बिना ''क्लस्टर आधारित आउटसोर्सिंग प्रणाली को कड़ाई से लागू किया जा रहा है जिसके कारण लैंडलाइन और ब्रोडबैंड सेवाओं पर भारी असर पड़ रहा है। क्लस्टर भुगतान समय पर किया जा रहा है और रास्ते से हटकर भी किया जा रहा है, जबकि अन्य सभी श्रम भुगतानों को बेरहमी से रोक दिया गया है।

एयूएबी द्वारा बार–बार अपील करने के बावजूद धन का आवंटन न होने और उचित ध्यान न देने के कारण ट्रांसमिशन सिस्टम चरमरा रहा है। गैर–भर्ती इकाइयों का विलय पूरा नहीं हुआ है, भले ही जनवरी, 2020 में निर्णय लिया गया था। इसने रखरखाव क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया है।

वीआरएस लागू होने के बाद कई गुना अधिक कार्यभार से कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। लेकिन, श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल '**पुनर्गठन**' के नाम पर कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने के कदम उठा रहे हैं।

पुनर्गठन के नाम पर, एक्जीक्यूटिव और नॉन–एक्जीक्यूटिव संवर्गों के लिए सभी पदोन्नति रोक दी गई हैं। श्री पी. के. पुरवार सीएमडी बीएसएनएल ने कर्मचारियों की पदोन्नति पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया है और इस तरह उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।

बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएषनों ने सब्सिडियरी टावर कंपनी के गठन का पुरजोर विरोध किया है और इसे रोक दिया है। लेकिन, श्री पी. के. पुरवार सीएमडी बीएसएनएल ने बीएसएनएल टावर कंपनी (बीटीसी) के नाम से गुप्त रूप से इसका संचालन किया है।

बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएषनों ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का कड़ा विरोध किया है। लेकिन, श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, पिछले दरवाजे से बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के लिए गुप्त रूप से कदम उठा रहे हैं। एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं को बीएसएनएल ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है। एमटीएनएल एक्सचेंज और ट्रांसमिशन उपकरण बीएसएनएल नेटवर्क/सीडीआर/एनजीएन से गुप्त रूप से एक–एक करके जुड़ रहे हैं। इसके अलावा, एमटीएनएल के निदेशक मंडल का बीएसएनएल के निदेशक मंडल में गुप्त रूप से विलय किया जा रहा है। कर्मचारियों को वैध सेवा लाभों से वंचित करने के लिए, विलय पिछले दरवाजे से संचालित किया जा रहा है। ये सभी श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल के दिमाग की पैदाइष हैं।

बीएसएनएल बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शक्तिहीन हो गए हैं और वे कोई निर्णय नहीं ले सके। मुख्य महाप्रबंधकों और क्षेत्रीय इकाइयों की राय को केवल नजरअंदाज किया जा रहा है और उसे दरकिनार कर दिया जा रहा है।

एमटीएनएल के केवल दो सर्किल हैं, दिल्ली और मुंबई। श्री पी. के. पुरवार, एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में इसके पुनरुद्धार के लिए कुछ नहीं कर सके। बल्कि एमटीएनएल अब ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए, श्री पी.के. पुरवार के नेतृत्व में बीएसएनएल के पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है।

विस्तृत चर्चा के बाद एयूएबी ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:–

(1) एयूएबी मांगपत्र पर आंदोलनकारी कार्यक्रम जारी रखेगा।
(2) एयूएबी को माननीय संचार मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखना चाहिए, जिसमें बीएसएनएल के सीएमडी श्री पी. के. पुरवार की मनमानी कार्रवाई पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, जिससे बीएसएनएल की स्थिति और खराब हो गई है।
(3) श्री पी. के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, जो कंपनी और उसके कर्मचारियों के भविष्य के लिए अपूरणीय क्षति कर रहे है, उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका को संमझाते हुए एक विस्तृत पंफ्लेट प्रकाषित किया जाना चाहिए और कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।
(4) श्री पी.के. पुरवार को सीएमडी बीएसएनएल के पद से हटाने की मांग करते हुए 06.10.2021 को एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा।
(5) मांगपत्र के निपटारे की मांग को लेकर 26.10.2021 को काला झंडा/काला–बैज धारण कर प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मांगपत्र में श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल को हटाने की मांग को भी शामिल किया जाएगा।

पी. अभिमन्यु
संयोजक, एयूएबी।

चंदेश्वर सिंह
अध्यक्ष, एयूएबी